

**Fourteenth Loksabha****Session : 4****Date : 10-03-2005****Participants : [Singh Dr. Manmohan, Advani Shri Lal Krishna](#)**

Title: Further discussion on the Motion of Thanks on the President's Address moved by Shri Pawan Kumar Bansal and seconded by Shri Ajay Makan on the 2<sup>nd</sup> March, 2005 and the amendments thereto moved on the 9<sup>th</sup> March, 2005. (Motion adopted and amendments negated).

**12.30 hrs.***The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past**Twelve of the Clock.**(Mr. Speaker in the Chair)***MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS – contd.**

MR. SPEAKER: I appeal to all the sections of this honourable House to please cooperate. If there are issues to be discussed, let us do it in a proper manner. Please give notice to me. I cannot promise as to what will happen but I will consider it. Give me an opportunity.

We will now take up the discussion on Motion of Thanks on the President's Address. Hon. Leader of Opposition, Shri L.K. Advani, may speak now.

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है, उसकी बहस कल देर रात तक चलती रही। मुझे सचिवालय से जानकारी मिली कि 48 सांसदों ने इस बहस में अब तक भाग लिया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तर देने से पहले आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, जिससे कि मैं अपनी बात रख सकूँ, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इस पर निर्णय परम्परा के अनुसार सर्वसम्मत समर्थन इस प्रस्ताव का होता है। राष्ट्रपति जी को हम सब, सरकार और विपक्ष मिल कर धन्यवाद देते हैं, लेकिन यह जो बहस है, यह पिछले अभिभाषण और आज के अभिभाषण के बीच में जो काल बीता होता है, उस पर देश की स्थिति क्या रही, क्या प्रगति हुई, कमजोरियाँ क्या हुई, सरकार की उपलब्धियाँ क्या हुई और फिर आगे के बारे में सरकार क्या सोचती है, इस पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। इसलिए सरकार जब राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करती है तो उस पर काफी समय पूरी केबिनेट बैठ कर चर्चा करती है और उसके बाद वह सांसदों के सामने रखी जाती है। मैं सबसे पहले पिछले दिनों में जो भयंकर दुर्घटनाएँ हुई, जैसे सुनामी की हुई, जिसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में है। उसमें जो परिवार आहत हुए, जिनकी मृत्यु हुई, उनके प्रति सारे सदन के साथ अपनी संवेदना जोड़ता हूँ। जिन्होंने सुनामी की दुर्घटना के समय देश और जनता की सेवा की, उसमें खास करके हमारी जो सेनाएँ थीं, जैसे नौवी, कोस्टल गार्ड्स और पैरामिलिट्री फोर्सस थीं, जिन-जिन प्रदेशों में सुनामी का प्रभाव हुआ, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी और सिविलियन फोर्सस थे, उन्हें मैं बधाई देना चाहूँगा।

उनके कार्य के कारण विश्व भर में हमारी यह साख बनी है कि इस प्रकार की भयंकर दुर्घटना के समय भी यह देश अच्छा कार्य कर सकता है और उसमें एन.जी.ओज़ ने जो योगदान दिया, उसका भी मैं थोड़ा उल्लेख करना चाहूँगा। आज ही गृह मंत्री ने इस

मामले में अभी एक वक्तव्य दिया है कि हम कानून के द्वारा एक डिजास्टर मैनेजमेंट एथॉरिटी क्रिएट करने जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उड़ीसा में जो भयंकर साइक्लोन आया था या गुजरात में भयंकर भूकम्प हुआ था, उसके बाद से लेकर हमारे यहां पर इसकी चिन्ता होती रही और चिन्ता करके एन.डी.ए. की सरकार ने श्री शरद पवार के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। आप उसके उपाध्यक्ष थे, हमारे प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष थे और उसने जो सिफारिशें कीं, मैं मानता हूँ कि उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यही थी, जिसका आज यहां पर उल्लेख शिवराज जी ने किया कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट एथॉरिटी स्टेचुटरी उसे बनाया जाये और वह हम करने जा रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं इस बात का उल्लेख करूंगा कि यह कल्पना केवल केन्द्रीय सरकार के लिए नहीं थी, कल्पना यह थी कि इस प्रकार की एथॉरिटी केन्द्र में भी बने और स्टेट्स में भी बने। मुझे खुशी है कि गुजरात ने इस मामले में पहल की और गुजरात में जो इस प्रकार की डिजास्टर मैनेजमेंट एथॉरिटी भूकम्प के बाद बनी, उसने बहुत अच्छा काम किया है और जिसकी प्रशंसा विदेश में भी काफी लोगों ने की, जिन्होंने उनका काम देखा है।

मित्रो, मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ कि हम चाहे आगे चलकर जो रीकंस्ट्रक्शन का काम होगा, उसमें भले कोई विदेशी सहायता करे... (व्यवधान) लेकिन जहां तक रिलीफ का सवाल है, रैस्क्यू का सवाल है, हमारी सामर्थ्य है, हमें कोई विदेशी सहायता नहीं चाहिए, यह सरकार ने निर्णय किया, यह ठीक किया, अच्छा किया। मैं तो यह भी मानता हूँ कि हमने सुनामी के बाद न केवल अपने यहां की व्यवस्था ठीक की, लेकिन पास के हमारे जो श्रीलंका जैसे देश हैं, जो कि भयंकर रूप से ग्रस्त थे, यों तो हमारे देश के तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल के अलावा जहां सबसे अधिक क्षति हुई, वह अण्डमान निकोबार आईलैंड्स में थी, लेकिन श्रीलंका और पड़ोस में भी ... (*Interruptions*)

**PROF. M. RAMADASS (PONDICHERY):** Pondicherry was also affected.

**SHRI L.K. ADVANI :** Yes, Pondicherry was also affected. I had occasion to visit Pondicherry when it happened. समाज का एक वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ और वह वर्ग फिशरमेन का, मछुआरों का वर्ग था। यह परिवर्तन एन.डी.ए. की सरकार के समय किया गया, उससे पहले disaster control, disaster mitigation and disaster management used to be the responsibility of the Ministry of Agriculture. क्योंकि, यह माना जाता था कि डिजास्टर चाहे हिन्दुस्तान में सबसे अधिक आता है, वह सूखा आता है या बाढ़ आती है, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार के अनुभव हुए, उसके आधार पर निर्णय हुआ कि यह कार्य प्रमुख रूप से गृह मंत्रालय में रहे तो ज्यादा उपयुक्त होगा, चाहे बाकी मंत्रालयों की सहायता लेनी हो तो लेनी चाहिए। तब से लेकर यह परिवर्तन हुआ है।

मैं चाहूंगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के संदर्भ में जो कानून हम बनाने जा रहे हैं, वह स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए और स्टैंडिंग कमेटी उस पर विचार करके फिर इसको यहां पर लाये, यह ज्यादा उपयुक्त होगा। स्टैंडिंग कमेटी विश्व भर में जो इस प्रकार के एनोलॉगस लॉज़ को, उन लॉज़ को भी देखकर फिर निर्णय करे। यों तो जिस समय कानून बनाया गया था, उस समय भी इस बात की जांच की गई थी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में नोर्थ ईस्ट का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि

राष्ट्रपति जी के भाषण में उत्तर-पूर्व का उल्लेख है जिसमें कहा गया है कि "My Government have infused a new sense of belonging among the various disaffected groups, especially in the North-Eastern States and among the tribal communities across the country." मैं नहीं जानता हूँ कि यह जो दावा किया गया है, इस दावे में सरकार भी विश्वास करती है या नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि पिछले दिनों में जो डिसएफेक्टिड ग्रुप्स उत्तर-पूर्व में हैं या अन्य स्थानों पर हैं, जैसे जम्मू-कश्मीर में हैं, उनमें से जो लोग मुझे मिले हैं, उन्होंने असंतो प्रकट किया है। नार्थ ईस्ट के लोग भी असंतो प्रकट करते रहते हैं और उत्तर-पूर्व में जैसी स्थिति बिगड़ी है, उससे कोई अपरिचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा, जब वे जबाब दें कि एनएससीएन (आई-एम) के साथ जो वार्ता चल रही है उसमें कितनी प्रगति हुई है और क्या हुई है? इतना मैं जरूर जानता हूँ कि एनएससीएन (आई-एम) के लोग अभी-अभी फिर से मुझ से आ कर मिले थे, जब वे दिल्ली आए थे। उनकी बातों से लगता था कि उनमें असंतो है, क्योंकि चर्चा की प्रगति ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जब उत्तर देंगे तब इस पर प्रकाश डालेंगे। जम्मू-कश्मीर पर भी बातचीत शुरू हुई और हरियत कांफ्रेंस से भी जो बातचीत हुई, जो राउंड्स हुए, कम से कम उस समय उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि हमारी बातचीत एनडीए की सरकार से संतोजनक हुई थी। आज क्या स्थिति है, मैं नहीं जानता हूँ। सिर्फ अखबारों से ही पता चलता है। उस मामले में अधिकृत

रूप से आज प्रधानमंत्री बताएंगे, तो हमको संतोहा होगा कि वहां पर बातचीत करने का जो प्रयत्न है, वह केवल मात्र किसी एक वर्ग से नहीं, बल्कि सब वर्गों से, जम्मू के लोगों से, लद्दाख के लोगों से और वहां के कश्मीरी पंडितों से वार्ता करते हुए हम कहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि जम्मू-कश्मीर के संबंध में जब वार्ता की बात होती है तो मुख्य रूप से लोगों को भारत-पाकिस्तान ध्यान में आता है। हम समझते हैं और एनडीए की सरकार समझती थी कि इस मामले में जम्मू-कश्मीर के भीतर भी एक मत नहीं है। कई अलग-अलग विचार हैं। कुछ लोग इस मत के हैं, खास कर के जम्मू में धारा 370 होनी ही नहीं चाहिए। दूसरे कहते हैं कि धारा 370 बहुत ही सैक्रोसेंट है, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। कुल मिला कर हमने यह सोचा कि हम सबसे बात करेंगे और सबसे बात करने के बाद आंतरिक दृष्टि से जो उपयुक्त होगा वह करेंगे और फिर भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में संसद का जो एक प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को ध्यान में रख कर ही हम पाकिस्तान से बात करेंगे। इस मामले में मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सरकार की स्थिति को स्पष्ट करें।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया है कि हमारा कमिटमेंट है कि हम ग्रामीण भारत को एक न्यू डील देंगे। यह बहुत अच्छी बात है। ग्रामीण भारत को न्यू डील देने की जो बात कही गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। यद्यपि कभी-कभी ऐसा लगता है कि ग्रामीण भारत और महान भारत सिर्फ शब्द बन जाते हैं। मुझे इस बात का संतोहा है कि एनडीए की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो महत्व दिया उसमें दो प्रमुख हिस्से थे - एक, देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना; दूसरा, गोल्डन ट्राइएंगल क्रिएट करना। नार्थ-वैस्ट, नार्थ-साउथ, ईस्ट-वैस्ट कोरिडोरस क्रियेट करना, ताकि हम कह सकें कि आज विश्व स्तर के हाईवेज़ हमारे यहां पर हैं। वह काम काफी प्रगति कर गया और अभी भी प्रगति कर रहा है। मैंने नोटिस किया कि आपने इस बात का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा है "The Government has decided to grant greater autonomy to the National Highways Authority of India while taking steps to make it more professional and efficient. The rate of completion of road construction under the national highways programme, especially the Golden Quadrilateral and the North-South and East-West corridors, has been speeded up." मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन मुझे खेद है कि एक तरफ तो कहते हैं कि रूरल इंडिया को न्यू डील देंगे। मैं इन हाईवेज़ के प्रोग्राम्स को महत्वपूर्ण मानता हूं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को मानता हूं।

जिसमें सरकार द्वारा संकल्प किया गया कि हम सन् 2007 से पहले हिन्दुस्तान के एक-एक गांव को पक्की सड़क से जोड़ेंगे। इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं कभी सोचता हूं कि क्यों ऐसा होता है। यह प्रधान मंत्री सड़क योजना है। एनडीए की सरकार की यह भी योजना थी तब भी उसका जिक्र है। लेकिन दूसरी योजना का नाम प्रधान मंत्री सड़क योजना है। क्या प्रधान मंत्री शब्द से परहेज है?... (व्यवधान) मैं नहीं जानता लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के संदर्भ में जो कुछ निर्णय किए गए और जिनके बारे में राज्यों को सहायता भी बहुत दी गई, उसकी प्रगति क्या हो रही है, इसकी हमें जानकारी मिलनी चाहिए क्योंकि मैं मानता हूं that in so far as road construction is concerned, in so far as infrastructure is concerned, that is far more important than even these Golden Quadrilateral and North-South and East-West Corridors.

यह मैंने कैजुअली जिक्र किया। मैं प्रधान मंत्री जी का बहुत आदर करता हूं। लेकिन प्रधान मंत्री इनविज़िबल हों, दिखाई न दें, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

आज प्रातःकाल ही मैं इंडियन एक्सप्रेस देख रहा था। उसमें एक लेख था। मुझे तकलीफ होती है। अगर आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी क्योंकि यह सोचना कि उसे देउबा से कम्पेयर करना या इससे करना और कहना कि टाइगर्स लुप्त हो रहे हैं तो प्रधान मंत्री लुप्त हो रहा है। यह जिस प्रकार की भाषा है, यह ठीक है कि जर्नलिस्टिक स्टाइल में उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है। लेकिन this kind of writing that continues throughout is something that, I would think, Dr. Manmohan Singh must think about it and a person who has such a high credibility in the country must think about it. ईमानदारी के नाते, प्रतिभा के नाते वह केवल अपनी अर्थोरिटी अफर्म करें तो इस प्रकार की राइटिंग बंद हो जाएगी। He is the Prime Minister, the supreme executive in the country. आपको मुझे कहना पड़े कि मुझे पता नहीं। हुआ है, पिछले दिनों छोटी-छोटी बातें ऐसी हुई हैं कि मुझे पता नहीं, जानकारी करनी पड़ेगी। अब मैं गृह मंत्री जी से सम्पर्क करूं या किसी और से सम्पर्क करूं... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मेरी जवाबदारी एनडीए की सरकार में प्रमुख रूप से आंतरिक सुरक्षा से संबंधित थी और राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्पष्ट लिखा गया है **that the three main areas of challenge to our national security are cross-border terrorism in Jammu and Kashmir, insurgency in the Northeast Region and naxalite violence in some States.** यह दावा किया गया है कि स्थिति कंट्रोल में है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि एक मौलिक गलती हुई है, जिस समय सरकार ने संभाला। जब उन्होंने नक्सलाइट वॉयलेंस को मान लिया कि प्रमुख रूप से यह लॉ एंड ऑर्डर प्राब्लम है जिसको स्टेट्स को डील करना चाहिए, वह जिस ढंग से करना चाहे, करे। इस अभिभाषण में भी कहीं पर इसका जिक्र है कि वह स्टेट्स का मामला है, स्टेट्स डील करे जैसे करना चाहे। बातचीत करना चाहे तो बातचीत करे, अगर उन पर से पाबंदी हटाना चाहे तो पाबंदी हटाए और हटाई है। आंध्र प्रदेश में नक्सलाइट वॉयलेंस इस हद तक गई कि वहां के तत्कालीन मुख्य मंत्री के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ और उनको मारने की कोशिश की गई लेकिन वे बाल-बाल बच गए। उसके बाद से लेकर चुनाव में एक प्रकार से आज जो सत्ता पक्ष है, उसमें उनकी सहायता ली गई और लगता है कि उनको वचन दिया गया कि अगर हम आएंगे तो आपके ऊपर से पाबंदी हटा देंगे। जयपाल जी कहते हैं, नहीं। बहुत अच्छी बात है, आपने नहीं किया। लेकिन जो कुछ उस समय हुआ कि हम किसी भी टीडीपी और बीजेपी के वर्कर को कैम्पेन नहीं करने देंगे।

अगर कोई करेगा तो हम उसे मार देंगे - यह बयान दिया गया और यही हुआ। वहां पर हमले हुए, इसके कारण आपकी जीत हुई या हमारी हार हुई। मैं कहता हूँ कि जहां पर इस प्रकार के तत्वों की राजनीतिक दृष्टि से सहायता ली जाएगी, चाहे वह आंध्र प्रदेश में हो। ... (व्यवधान) चाहे वह आंध्र प्रदेश में हो या असम में हो, वहां पर इसके स्वाभाविक दुपरिणाम आने वाली सरकार को भुगतना पड़ेगा, जो आज हम भुगत रहे हैं। यह केवल वहां पर सीमित नहीं होगा। **Naxalite violence is a phenomenon.** मैं नहीं मानता कि इस फिनोमिना के बारे में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की प्राब्लम है और कोई डायमेंशन नहीं है, और भी आयाम हैं। उन आयामों को डील करते हुए कभी भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसके कारण उनको रिस्पेक्टिबिलिटी मिल जाए।

यहां पश्चिम बंगाल के लोग बैठे हैं, ये आपके सहयोगी हैं, उनसे कुछ सीखिए। उन्हें नैक्सलाइट वॉयलेंस कहा जाता है। नैक्सलाइट वॉयलेंस नक्सलवाड़ी में नहीं है। इसका कारण है, जिनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। मैं मानता हूँ इसका कारण यह है कि जिनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, वह आरंभ में मार्क्सवादियों के खिलाफ था, वह स्टेट के खिलाफ नहीं था। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ मुकाबला किया, नहीं तो रिस्पेक्टिबिलिटी ऐसी थी कि यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में अच्छे से अच्छे छात्र नैक्सलाइट आंदोलनों में चले जाते थे। आज मुझे यह दिख रहा है कि आंध्र प्रदेश में आपने वैसी ही स्थिति पैदा की है। यह बहुत भयंकर, घातक और हानिकारक है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि इन मामलों में **do not take partisan decision. Always take the advice of all political parties, what should be done and what should not be done.** इतना ही नहीं इंटरनल सिक्योरिटी प्राब्लम्स हैं, चाहे टेरेरिज्म हो, चाहे इन्सरजेंसी इन नार्थ ईस्ट हो, चाहे जम्मू-कश्मीर में आईएसआई एजेंट्स की प्राब्लम हो, इन सभी मामलों में **Always take the advice of those who are fighting against them.** जो उनके साथ जूझ रहे हैं, जो अधिकारी जूझ रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सिस जूझ रही हैं, उनकी एडवाइज ज़रूर लें। निर्णय आपको करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्णय सरकार करती है। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले छः साल में एनडीए सरकार में इंटरनल सिक्योरिटी के इश्युज के बारे में, चाहे वह टेरेरिज्म की प्राब्लम हो, चाहे इल्लीगल इमिग्रेशन की प्राब्लम हो, इन सब में देश भर के डीजी पुलिस, इंटेलिजेंस फोर्सिस के प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इन सबसे सलाह करके निर्णय करते थे। ऐसा नहीं कि एक स्टेट अपने आप फैसला कर लेता थी। सन् 1998 में एनडीए सरकार ने काम किया **in respect of Naxalite violence was to hold a conference of all Naxalite affected States in Hyderabad. All of them were called there.** और उनके साथ मिल कर हमने एक कोओरडिनेटिड स्ट्रेटेजी बनाई। स्ट्रेटेजी ही नहीं बनाई ... (व्यवधान) स्ट्रेटेजी ही नहीं बनाई बल्कि कोओरडिनेशन कमेटी भी बनाई जिसमें इन सभी स्टेट्स के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शामिल थे। इन सभी स्टेट्स में इनके ऊपर सेंटर के यूनियन होम सेक्रेट्री थे और **without fail, every three months, this Coordination Committee used to meet to take account of what has transpired** कि कहां पर कितना कंट्रोल हुआ है और कहां पर नहीं हुआ है। इस काल में अचानक **Naxalite violence spreads to Karnataka, policemen are killed there. Naxalite violence spreads to Uttar Pradesh, policemen are killed there.** इसका परिणाम यह हुआ है क्योंकि घोणा की गई कि यह तो स्टेट का मामला है, स्टेट जो करना चाहे करे। स्टेट ने पीपुल्स ऑफ वार ग्रुप पर आंध्र प्रदेश में बैन हटा दिया। **Even without insisting** पीपुल्स ऑफ ग्रुप से बातचीत शुरू कर दी। एके-47 लेकर लोगों को मारते रहेंगे और बातचीत नहीं करेंगे। **This is the minimum the world over any Government that has talked to people who are in the path of violence, the minimum** कि हम आपसे बात करेंगे।

पहले हथियार छोड़ो, पहले हिंसा बंद करो, उसके बाद बात करो। बात करना जरूरी है, मैं बात करने के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सबसे बात करने के पक्ष में हूँ लेकिन बात करते हुए जो मिनिमम सावधानी बरतनी चाहिए, वह भी बरतने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है कि वह अपना ए.के. 47 लेंगे, नहीं तो दुनिया भर में कौन सी अंडर ग्राउंड आर्गनाइजेशन ऐसी होगी जो अंडरग्राउंड होने के बाद बैन हटते ही पहली रैली करे और उसमें लाखों लोग ऐसे इकट्ठे हों जैसे आंध्र प्रदेश में पीपल्स वार ग्रुप में इकट्ठे हुए। ऐसा कभी नहीं होता लेकिन हुआ है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इंटरनल सिक्युरिटी के मामले में इस सरकार का एप्रोच पूर्णतया विफल रहा है। **It has completely failed. There is a need to review it again.**

प्रधान मंत्री जी उसे रिव्यू करे। मेरी सलाह है कि रिव्यू करते हुए अन्य पार्टियों से भी आप सलाह करें।

**THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL):** May I intervene? आप जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल दुरुस्त बात है। हम उसका विरोध करने के पक्ष में नहीं हैं। मगर मैं सम्मानीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि हैदराबाद में नैक्सलाइट्स अफैक्टेड स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है। हमारे जो गृह सचिव हैं, वे उन सभी स्टेट्स के गृहसचिवों से बात करते हैं। उसके बाद हमारे जो इंटरनल सिक्युरिटी के स्पेशल सैक्रेट्री हैं, उनसे भी बात करते हैं। जैसा आपने कहा कि बात होनी चाहिए मगर बात होते समय कोई हथियार लेकर नहीं जाना चाहिए, यह बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप जो कह रहे हैं, वह हो रहा है। अगर सिर्फ इतना ही बताने की कोशिश हुई कि यह नहीं हो रहा है तो वह गलत है। ...(व्यवधान)

**SHRIMATI TEJASWINI SEE RAMESH (KANAKAPURA):** Even your NDA partners are attacked in Andhra Pradesh. Do not forget this. ... *(Interruptions)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, तेलगू देशम पार्टी के 46 लोग मारे गये। ...(व्यवधान)

**MR. SPEAKER:** Do you think you are helping him?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मेरी बेसिक आपत्ति यह है कि जिसको हमने एक कोआर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी के अधीन बनाया, इस सरकार ने आते ही कहा कि यह राज्य का मामला है और राज्य फैसला करे कि वह क्या करना चाहती है ? ...(व्यवधान)

**MR. SPEAKER:** He is giving his view. He is entitled to give his view.

**SHRI L.K. ADVANI :** Otherwise, how do you explain that the People's War Group is legalized in one State and not in the other States? I know Chhattisgarh. I know States like Jharkhand where they will not legalize it. They continue the ban because you decided that it would be a State-wise issue. We decided this is not a State-wise issue. This is something that has application to all the States affected by naxalism. प्रधान मंत्री जी, आज की स्थिति में यह स्थिति और भी गंभीर हो गयी क्योंकि नेपाल में जो दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना के कारण वहां पर माओवादियों की ताकत बढ़ गयी है। माओवादियों का लक्ष्य केवल नेपाल नहीं है। उनकी ताकत बढ़ने के कारण आज नेपाल के साथ-साथ पूरे बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक और जिसको अब कर्नाटक तक एक्सटेंड किया जा रहा है, वह सारा का सारा हिस्सा अफैक्टेड है। ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार के निर्णय करें कि वहां पीपल्स वार ग्रुप पर से प्रतिबंध हटा दें, तो यह सरासर गलत निर्णय है। ये निर्णय नहीं होने चाहिए थे।

मैं नेपाल के ऊपर बाद में बात करूंगा। नेपाल में हमारी ऐसी नीति होनी चाहिए जो माओवादियों को वहां पर ताकत न दे। हां, मेरी यह राय है कि वहां पर संवैधानिक मोनार्की, **Constitutional monarchy and multiparty democracy are the two pillars of peace and security of Nepal. Both should be strengthened.** मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के नाम पर अगर हम मोनार्की को वीक करेंगे तो हम माओवादियों को बल देंगे। यह कभी नहीं होना चाहिए। इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, एक विषय ऐसा है जिससे मेरा व्यक्तिगत संबंध है। मेरा जन्म कराची में हुआ। मैं सिन्ध का मूल निवासी हूँ। विभाजन के बाद मैं इस ओर आया। विभाजन के बाद 1950 में जब देश का राष्ट्रगान स्वीकार हुआ और श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर का जन-गण-मन स्वीकार किया तो उसके बाद कभी-कभी यहां से या कभी वहां से आवाज उठती थी कि इसमें पंजाब, सिन्ध, गुजरात, मराठा क्यों होना चाहिए ?

**13.00 hrs.**

सिन्धु क्यों होना चाहिए ? सिन्धु तो अब हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं रहा है और इसकी चर्चा होती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब पहले-पहले किसी ने बहस की थी, पहले किसी ने वक्तव्य दिया तो उसका जवाब स्वयं पंडित नेहरू जी ने दिया था और उन्होंने कहा था कि सिन्धु के बिना हिन्द नहीं होता। मेरे पास इस समय वह वक्तव्य नहीं है लेकिन डिसकवरी ऑफ इंडिया में पंडित जी ने जो कुछ कहा है, उसमें उन्होंने लिखा है :

"The word 'Hindu' is clearly derived from 'Sindhu', the old as well as the present Indian name for the Indus. From this 'Sindhu' came the words 'Hindu' and 'Hindustan' as well as 'Indus' and 'India'."

इतना ही नहीं, मैं मानता हूँ कि भारत की सिन्धु सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और इसीलिए हमारे यहां सिन्धु का उल्लेख केवल मात्र एक प्रान्त के नाते नहीं होता है, सभ्यता के नाते होता है और जब किसी संजीव भटनागर नाम के एक सज्जन ने सुप्रीम कोर्ट में 20 सितम्बर को एक पीआईएल फाइल की जिसमें कहा कि इसमें से सिन्धु शब्द निकालना चाहिए तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहा कि इस मामले में क्या आपने सरकार से बात की ? उनको कहा कि आप सरकार से बात करो तो उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री तथा विदेश मंत्रालय को एक-एक पत्र लिखा। उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने इस मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में उठाया। 4 दिसम्बर को फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि जवाब चाहिए। उसके बाद कहीं शायद 14 दिसम्बर को गृह मंत्रालय ने लिखा कि ऐसा कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। इतना ही जवाब दिया। 3 जनवरी को उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि सरकार ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है।

मुझे याद है कि उनके बारे में इस अखबार में पढ़ने के बाद मैंने स्वयं प्रधान मंत्री जी को 10 जनवरी को एक पत्र लिखकर कहा कि इसमें सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि क्यों इसमें से सिन्धु शब्द हटाया नहीं जाएगा। 7 मार्च को फिर से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी प्रकट की कि क्यों सरकार ने जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से 4 सप्ताह का समय मांगा गया है और न्यायालय ने दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इस मुद्दे का महत्व समझने का आग्रह भी किया गया है। मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार की क्या सोच है और क्या सरकार ने कुछ विचार किया है या फिर सुप्रीम कोर्ट ही सब निर्णय करेगा ? इन सब बातों से नाराजगी होती है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय करता है। एग्जीक्यूटिव जब कोई गलत काम करती है, कोई काम सही नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य हो जाता है कि वह हस्तक्षेप करे और जब वह डेमोक्रेसी की रक्षा में हस्तक्षेप करता है तो उस तरफ के हमारे मित्र नाराज हो जाते हैं। आज बहुत नाराज हो रहे थे। आज पहली बार हमने देखा कि सरकारी पक्ष के कारण सदन स्थगित हुआ और 5-10 मिनट में ही... (व्यवधान) पहले भी सरकारी पक्ष के कारण सदन स्थगित हुआ तो ठीक है, फिर आप विपक्ष को दो नहीं दे सकते हैं।... (व्यवधान)

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड के मामले को उठाने की आज आपने हमें परमिशन नहीं दी लेकिन ये इस बात को अपने भाण में ला रहे हैं, ... (व्यवधान) मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: But Mr. Advani, I am sure you would agree that all organs of the State should conduct themselves within their powers.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : लेकिन आज तक क्या कभी किसी पक्ष ने, किसी पार्टी ने, किसी सदस्य ने ज्यूडिशियरी के बारे में सवाल उठाया है ? ... (व्यवधान) कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनको होली कॉउ बनाकर रखना ही ठीक है। कुछ-कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनके बारे में चर्चा तो हो सकती है लेकिन लाइटली अगर हम खड़े हो सकेंगे, सेना के बारे अगर कुछ कहेंगे, ज्यूडिशियरी के बारे में कुछ कहेंगे तो I do not think, it is right. आपने जो किया है, वह ठीक किया है कि आपने किसी को परमिट नहीं किया, आपने किसी को अनुमति नहीं दी और इसके स्थान पर कहा कि मैं नेताओं को बुलाकर उनसे बात करूंगा, यह उचित तरीका है। लेकिन किसी को होली काउ बनाने से उसका कोई नुकसान नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में अगर लाइटली न बोला जाए, आलोचना को साधारणतः परमिट न किया जाए तो वह उचित होता है।... (व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : आपको भी इससे फायदा होगा।... (व्यवधान)

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): You cannot decide that.... (Interruptions)

MR. SPEAKER: The Speaker has said that he would decide.

... (Interruptions)

श्री लाल कृण आडवाणी : अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह उल्लेख है कि

"A Ministry for Overseas Indian Affairs has been created to give focused attention to issues related to the large diaspora of persons of Indian origin in different parts of the world. "

मंत्रालय बनाना ठीक है, उचित है। डायसपोरा की ओर हमने बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक कि प्रतिर्वा यहाँ पर इण्डियन्स ओवरसीज का एक कन्वेंशन आयोजित करना शुरू किया। यह कन्वेंशन तीसरी बार इस र्वा मुम्बई में हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। इसके बहुत-से लाभ हैं। इण्डियन्स ओवरसीज की र्वा पुरानी एक इच्छा रही है कि उनको दोहरी नागरिकता मिलनी चाहिए। इसे र्वा 2003 में एक कानून का रूप दिया गया है और उसमें इस बात की सावधानी रखी गयी है कि हमारे देश की सुरक्षा को कोई आंच न आए और इसीलिए सभी इण्डियन्स ओवरसीज को सामान्य रूप से दोहरी नागरिकता प्रदान कर देना, हमें उचित नहीं लगा। इस विषय पर हमने डा. सिंघवी के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई थी उसकी भी यही सिफारिश थी। इस कमेटी ने कहा कि जिन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हैं, जहाँ पर पहले से ही इस प्रकार के कानून हैं, जहाँ पर इस प्रकार की मांग है और हमारी सुरक्षा, इन चार बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशिफाइड देशों के ही इण्डियन्स ओवरसीज को दोहरी नागरिकता दी जानी चाहिए। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भाषण में इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि यह स्पेशिफाइड क्यों होनी चाहिए, सभी को दोहरी नागरिकता मिलनी चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आज यदि बांग्लादेश के सभी नागरिक जो यहाँ आए तो उनको दोहरी नागरिकता दे दी जाए, पाकिस्तान से जो लोग आए, उन सभी को दोहरी नागरिकता दे दी जाए और इसी तरह के कुछ अन्य देश हैं, जिनके नागरिकों को दोहरी नागरिकता देना हमारे देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा। इसकी चिन्ता करनी पड़ेगी और इसीलिए हमने स्पेशिफाइड देशों के इण्डियन्स ओवरसीज को ही दोहरी नागरिकता देने की बात की है।

महोदय, मैं जिस समय इस विषय को राज्यसभा में रख रहा था, उस समय डा. मनमोहन सिंह सदन में विपक्ष के नेता थे। महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इसको पढ़ना चाहूँगा।

MR. SPEAKER: Shri L.K. Advani, I hope you know the rules.

SHRI L.K. ADVANI : I know the rules. But because it is a substantial point which is relevant, I welcomed what he said. वहाँ पर जब मैं प्रस्ताव रखने ही वाला था, डिप्टी-चेयरमैन मैडम नजमा जी ने मुझे बताया कि इस विषय पर डा. मनमोहन सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि यह पहले ही डिसाइड किया गया था कि इस प्रस्ताव को बिना बहस के ही पास कर लिया जाएगा। उस समय डा. मनमोहन सिंह ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा था :

"While I am on this subject, Madam, I would like to say something. About the treatment of refugees after the partition of our country, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution and it is our moral obligation that if circumstances force people - these unfortunate people - to seek refuge in our country, our approach in granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal. I sincerely hope that the hon. Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to the Citizenship Act. "

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): I still stand by it.

श्री लाल कृण आडवाणी : महोदय, उसके बाद श्री शंकर राय चौधरी ने भी लगभग इन्हीं शब्दों में बहुत आग्रह के साथ यही बात कही, जिसका उत्तर देते हुए मैंने कहा :

Madam, I have taken note of what the Leader of the Opposition and Shri Shankar Roy Chowdhury have said and I am fully in agreement with the views that they have expressed. Very often in the past, we have faced this kind of criticism when we have adopted an approach of that kind.

I said that when we say that so and so is an illegal migrant and he should be sent back, but so and so has been persecuted there because he belonged to the minorities and, therefore, in his case we would be willing to consider granting him citizenship, we were told that 'you are being communal, you are discriminating between one migrant and another migrant'. I said 'yes'. In this case, so far as the minorities of Bangladesh are concerned – and someone else later mentions that Pakistan also – I said 'yes, I take into cognizance of the fact that when partition took place, we undertook that so far as the Minorities in India are concerned, we will look after them; so far as the minorities in Pakistan and Bangladesh - Bangladesh came much later - are concerned, it will be their responsibility to look after them. If they have failed, then we owe it to the minorities in those areas to accept them as citizens here.

This is what I would like to say. I fully endorse this point. I hope that now, after coming to the Government, the hon. Prime Minister continues to hold the same view and would be willing to grant citizenship to all such minorities who have come to West Bengal or Assam or other places, and make a difference between them. ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष जी, अब मैं इस बात पर आना चाहता हूँ जिसकी चर्चा सुबह-सुबह हमारे कई मित्र कर रहे थे। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक तमिल कविता भी कही है। कुछ लोग टिप्पणी कर सकते हैं कि वह तमिल की कविता तो कैबिनेट ने एप्रूव नहीं की होगी। खासकर लीगलस्टिक ब्यू का कोई होता है, वह करता ही है। मैं तमिल नहीं जानता, लेकिन मुझे कहा गया, उस कविता का जो पहला सेंटेंस है, वह है - नाम एंगे इरिक्किरोमा।... (व्यवधान) हम कहां पहुंचे हैं! Where are we? ... (*Interruptions*) Am I right?

This is the question that the Government must ask itself. कहां पहुंचे हो नौ-दस महीने में, यहां पहुंचे हो कि जिस राज्यपाल का आप समर्थन कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो पिछले चार-पांच दिनों में, उस पर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है, ... \* क्यों डिफेंड करते हो ? हम प्रधान मंत्री जी से बार-बार कहते हैं कि अगर किसी ने किया भी है तो खोजना होगा।... (व्यवधान)

श्री तरित बरन तोपदार (बैरकपुर) : जब आपने राज्यपाल के बारे में बात करने से यहां मना किया है, तो यह क्यों बोल रहे हैं।... (व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : अगर इस पर बोलना है तो फिर सदन में चर्चा कराई जाए। आपने पहले ही कह दिया है कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती, फिर भी यह बोल रहे हैं।... (व्यवधान)

SHRI L.K. ADVANI : Ever before in the political history of India, has a court made – the Supreme Court, not any other court – the Supreme Court made an observation of this kind in respect of a constitutional authority like the Governor? ... (*Interruptions*)



SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, this is not correct. ... (*Interruptions*) He cannot say it. ... (*Interruptions*)

SHRI L.K. ADVANI : Sir, I am not yielding. ... (*Interruptions*)

MD. SALIM : Sir, this is not correct. ... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Shri Advani, you may like to yield to the Leader of the House.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE ) : Sir, he has made a remark against the Governor ... (*Interruptions*) It is not correct. Shri Advani, please correct your statement. ... (*Interruptions*)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, the Governor should not be dragged here. ... (*Interruptions*)

MD. SALIM : Sir, I need your protection. Please permit me to speak for a minute. ... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : I will certainly look into it. No derogatory reference should be made to a constitutional authority like Governor.

... (*Interruptions*)

\* Not Recorded.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, a ruling of the Supreme Court cannot be wrongly interpreted here and the position of a constitutional authority cannot be challenged in this manner without giving a proper notice to you. ... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : I said that I have omitted it. It is out of record.

... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Sir, the apex court has made some other observations also. ... (*Interruptions*)

SHRI L.K. ADVANI : For the first time in the political history of this country ..... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Shri Advani, how long will you take?

श्री लाल कृण आडवाणी : नहीं तो हम कितनी बार किसी शिकायत को लेकर राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं। राष्ट्रपति जी को कहते हैं कि यह काम गलत हुआ है या यह काम गलत हो रहा है इसलिए यह काम नहीं होने देना चाहिए। ... \*

MR. SPEAKER : No reference to Rashtrapatiji. I have deleted it. You cannot make any reference to the Rashtrapati.

... (*Interruptions*)

SHRI L.K. ADVANI : Mr. Speaker, Sir, may I show you the rule? ... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: No. It has been deleted. I have expunged it.

... (*Interruptions*)

SHRI L.K. ADVANI : Mr. Speaker, Sir, I am not trying to influence the debate, if I use the Rashtrapati's name. ... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You are such an experienced person.

... (*Interruptions*)

\* Not Recorded

SHRI L.K. ADVANI : This is a matter of fact that he summoned. ... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Maybe, but reference to him is not relevant. I have given my ruling.

... (*Interruptions*)

SHRI L.K. ADVANI : I accept your ruling. I accept all your rulings even though I may not agree with them. ... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Thank you.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : ... \*

अध्यक्ष महोदय: वह भी नहीं आएगा।

... (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : एक-एक करके जितने लोग यहां सामने बैठे हैं, सब ने गवर्नर के डिसिजन से अपने आप को डिस्टैंस किया है। वे कहते हैं कि हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है। हमने उनसे नहीं कहा है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आडवाणी जी को अपना भाण खत्म करने दीजिए। आप बैठिए।

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You have taken 45 minutes.

SHRI L.K. ADVANI : Sir, I will conclude. ... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I have always been saying that we need not agree with each other's views. He is expressing his view. The Prime Minister will reply. I am sure, he will deal with this.

... (*Interruptions*)

श्री लाल कृण आडवाणी : श्री सिब्ले रजी, झारखंड के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वह शायद रायबरेली के मूल निवासी हैं। वह लखनऊ गए थे। वह जब लखनऊ गए तो पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने जो कुछ कहा मेरे पास "दैनिक जागरण" पत्र की कोटिंग है जिस में उन्होंने कहा है कि मैं राज्यपाल के पद पर हूँ, मैं बिल्कुल मर्यादा में रह कर बात करूँगा। उन्होंने मर्यादा में रह कर जितनी बातचीत की, उसका अर्थ उन्होंने कल लगाया। उनकी ओर से जब पत्रकारों को बुलावा भेजा गया

\* Not Recorded

तो हमें लगा कि कोई धमाका होने वाला है। किन्तु उन्होंने बाद में बड़ी सावधानी से संकेत दे दिया कि \*

MR. SPEAKER: That is not binding on anybody.

... (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : No. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: This cannot go on record. The Governor's statement cannot go on record.

... (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, this is not correct. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: On the basis of a newspaper, you cannot make an imputation on the Governor.

... (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI : Since when has this rule been there? ... (Interruptions) \*

MR. SPEAKER: On the basis of newspaper, one cannot make any comment on a constitutional authority.

... (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: You know that you cannot quote the newspaper. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have given my ruling.

... (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: You cannot rely upon the newspaper. ... (Interruptions)

श्री लाल कृण आडवाणी : आप जो निर्णय देंगे, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मेरा भाग्य चाहे कुछ भी हो लेकिन प्रधान मंत्री मेरी बातों पर विचार करेंगे। हिन्दुस्तान में जो लोग कभी बीजेपी की तारीफ नहीं करते थे, बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, इन दिनों वे सब के सब अचानक तारीफ कर रहे हैं, ...

\* Not Recorded

MR. SPEAKER: Without notice, you cannot mention these names. I am trying to protect ethics.

... (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI : Sir, I know that you are protecting ethics. I know the procedure. I know why it is being protected.

MR. SPEAKER: You mentioned some well-known journalists.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: You can say that many people have expressed similar views.

... (Interruptions)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने विस्तार से झारखंड के मामले में प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा था। प्रधान मंत्री जी ने मुझे उसका जवाब भी दिया। उन्होंने जवाब में कहा है कि आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उन्हें पार्लियामेंट में पूछिए। मैं उन्हें पूछने वाला था लेकिन जिस प्रकार की बात चल रही है, मैं उन्हें नहीं पूछना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कुल मिला कर हम को 1975 का स्मरण आता है। हमें ही नहीं जितने पत्रकार हिन्दुस्तान में हैं, जो साधारणतः हमारी आलोचना करते हैं, मैंने देखा है कि एमरजेंसी की घटना के बाद जब ऐसी कोई बात सरकार की ओर से होती है जिस में से आभास मिलता है कि लोकतंत्र को रोका जा रहा है, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया जा रहा है तो सब ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please sit down.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठिए । आडवाणी जी आप बोलिए ।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I am controlling them also. How should I do it? You kindly tell me the method to do it.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please sit down.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए । आपके नेता बोल रहे है । ठीक है, पहली दफा नहीं हुआ है ।

मना कर रहे हैं ।

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Mistry, please sit down. आप बोलिए ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । He is concluding his speech. He has already said that he is going to conclude his speech.

SHRI L.K. ADVANI : Sir, I am concluding my speech. आज प्रणव जी आए हैं, चिंतनशील हैं । मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आप यह मानकर चलेंगे कि देश का भला इसमें है कि देश भर में कांग्रेस पार्टी छा जाए तो इसी प्रकार की गलतियां करेंगे, जैसी कर रहे हैं । एक-एक करके हर प्रदेश में येन-केन-प्रकारेण कांग्रेस की सरकार कैसे आए, लगता है यही आपका लक्ष्य है। ...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): What did you do in Arunachal Pradesh?

MR. SPEAKER: Please keep quiet.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कुछ समय पहले इंडिया टुडे का कान्क्लेव हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री जी भी गए थे और मैं भी गया था । विषय बहुत विचित्र था । मुझे सवाल पूछा गया और कहा गया कि आप इस थीम पर बोलिए "Is good economics bad politics?" यह सवाल पूछा गया कि क्या सही अर्थनीति गलत राजनीति है? मैंने उसका उत्तर दिया कि यह सन् 2005 है, and this marks two anniversaries. The 50<sup>th</sup> anniversary of the resolution passed by the AICC in respect of economic policy -- commanding heights of the economy, जिसे अनडू किया था आज के हमारे प्रधानमंत्री ने सन् 1992 में। ...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): It is commanding heights of the economy of India.

SHRI L.K. ADVANI : Yes, I know it. Secondly, this is the 30<sup>th</sup> anniversary also of the emergency. The first was bad economics, and the second was bad politics. Today, I feel that while so far as economics is concerned the then Finance Minister continues to do what he proposed at that time. It is something, which we pursued, and you are continuing it. ठीक है उसके नुआएंसिस बजट स्पीच में आएंगे, दो आते हैं । But so far as bad politics is concerned, I have a feeling that even though after the emergency nobody again dare to impose an emergency, but the basic mindset which brought about the emergency that सारे हिंदुस्तान पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए वह सब आज भी है और बीजेपी के खिलाफ काम में आएगा । मैं एलाएंस को कहना चाहता हूं कि यह सबके काम आएगा । ...(व्यवधान) इसे लालू प्रसाद जी भुगत चुके हैं । आप फिक्र मत कीजिए । ...(व्यवधान) Therefore, I plead with the hon. Prime Minister to pursue on the same lines. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: He is concluding. This is his last sentence.

SHRI L.K. ADVANI : Let him pursue the same line, which we developed, in so far as the economy is concerned, but he should completely abandon this politics, if he has the power to do it; otherwise distance himself from it.

MR. SPEAKER: Now, hon. Prime Minister. Please, let us give each other a proper hearing.

DR. MANMOHAN SINGH : Mr. Speaker, Sir, I deem it a great privilege to be standing here today to express the gratitude of our Government to the respected Rashtrapatiiji for his address to Members of both Houses of Parliament.

Sir, this is a hard earned privilege for me since I have had to wait out the entire year to perform this happy task. I would like to take this opportunity to doubly thank the President -- for his Address last year and his Address this year.

Sir, last year, the Rashtrapathiji outlined the nature of the historic mandate that the constituents of the United Progressive Alliance had received from the people of our country. He also outlined the vision underlying the National Common Minimum Programme: A vision of share prosperity, of an inclusive society, of a caring polity. The President captured the essence of this philosophy in his Address to Parliament this year when he said that we want India to shine, but that it must shine for all.

Sir, this year, the President has outlined the many steps we have taken in office in a brief period of nine months to fulfil some of the most important promises we have made in the National Common Minimum Programme. Read together, the two Addresses of the President offer an overview of the political revolution that the United Progressive Alliance has authored in translating the mandate of the elections of 2004.

Mr. Speaker, Sir, the President has paid an eloquent tribute to all those who acted heroically in dealing with this disaster called 'Tsunami'. Our Armed Forces, our paramilitary forces, our State Governments and our own Central Government authorities acted with great speed to provide relief and then thereon from relief and succour to move on to the task of rehabilitation. I wish to join the hon. Leader of Opposition in paying tributes particularly to our Armed Forces, our Coast Guard, and our paramilitary forces for the heroic task that they have accomplished.

Before I go further, I listened very carefully to the advice of the hon. Leader of the Opposition. I respect him. He is a seasoned politician who has been in politics much longer than I have been. When he advised me that I was becoming an invisible Prime Minister, I must solemnly say that, that is a charge I do not plead guilty to. Whether a Prime Minister is visible or not visible should be judged from the conduct of our Government, and when I outline what we have achieved in nine months, it is for the House to judge.

However, I must say, Sir, wherever people of India were in distress in the last nine months, I along with Soniaji went there. When our Government was faced with a drought, I went to those areas where the intensity of the drought was so severe that farmers were committing suicides. When there were floods, I was there with the people of Bihar; I was there with the people of Assam. Similarly, I had been to Jammu and Kashmir twice in the last six or seven months. I was there in Andamans; I was there in Tamil Nadu; I was there in Kerala, and I was there in Andhra Pradesh when our people were faced with this Tsunami disaster. Therefore, our record speaks for itself.

If you permit me, Mr. Speaker, I will outline what we have achieved in the last nine months.

Mr. Speaker, Sir, many hon. Members who were able to participate in the debate on the Motion of Thanks to the President on his Address have made very important points. I have taken note of their sentiments. Due to shortage of time, I may not be able to reply to all the points but hon. Members have my assurance that the suggestions that have been made on the floor of this House will receive our most serious attention.

A question has been asked in this House as to what exactly we have done in these past nine months to redeem our pledge to the people. Let me say at the very outset that the President's Address should be read along with the Budget Speech of the Union Finance Minister and the Action Taken Report laid on the Table of the House by the hon. Finance Minister to fully appreciate the enormous work done by our Government in such a short period of time. To supplement this, our Government has also prepared a 'Report to the People', for the first time ever, that informs the general public as to what steps have been taken to implement the National Common Minimum Programme. Copies of this Report are being made available to every Member of Parliament. They are also being sent to every media organisation. Never before I believe has a Government been so transparent and proactive in keeping the public informed. I will be the last one to say that we have achieved everything. I recognise that we have miles to go but we will persevere and we shall overcome.

Mr. Speaker, Sir, Advaniji talked about the economic policies. Lot of things have happened in our country in the last 50 years. It is my sincere conviction that but for the solid foundation of our economy - the scientific infrastructure that Panditji created, the temples of learning Universities, Institutes of Management and Technology that Panditji created, the public sector investments that were made to promote self-reliance - we would not be where we are today.

Changes have been made in the economic policies. In every living society these changes have to be made. Panditji himself used to say that we are living in a dynamic world and we cannot be slaves all the time of the past. So we have made changes, but the basic thrust of our economic policy remains what was conceived at the time of our Independence - to promote a self-reliant, progressive, humane and egalitarian society.

On the economic front, our efforts to steer Indian economy on to a high-growth path are bearing fruit. Rashtrapatiji has referred to this in his address and this has been further elaborated upon in the Finance Minister's Budget Speech. Our Government was elected on the basis of the mandate that reflected dissatisfaction of 'aam admi' with the way his concerns were being addressed. That is why we have made fighting inflation and generating employment the two most important goals of our economic policy. I am happy to report that the rate of inflation has dipped below five per cent despite the drought and despite the sharp increase in international prices of petroleum products.

We have, at the same time, managed to create a growth momentum which has not only delivered a growth of almost seven per cent this year, but is likely to deliver equally impressive growth in the coming years. Our external profile is robust and International Credit Rating Agencies are upgrading our sovereign rating. The balance of payment position is as comfortable as never before. International trade is booming with exports rising at over 25 per cent in dollar terms in April-January, 2005.

Sir, what is more impressive is after many years of investment famine under the NDA regime, we see a clear revival of investment activities and consequently, there is a fine degree of confidence in

the future of our economy. This confidence has been bolstered by the growing recognition of the fact that our politics of inclusiveness is creating a more humane social basis for more equitable economic growth. The one area of concern is the high level of fiscal and revenue deficits of State and Central Governments and I sincerely hope that we can, by working together, evolve a national political consensus in dealing with this fiscal challenge. I am sure, Sir, that hon. Members will have an opportunity to debate further on this in the debate on the Union Budget.

Sir, to sustain this sense of optimism our Government has taken steps to create a more equitable economic framework, a framework within which all regions and classes will participate in growth process. There is no point in having a high rate of growth if the benefits are not shared by all sections of society, particularly the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, backward classes, minorities and women. This requires taking steps to empower them, investing in their skill enhancement to enable them to be active participants in the economy, providing a social-legal framework where their rights are recognised and protected and creating an atmosphere of belonging and inclusiveness.

Sir, the results of our efforts will, I am certain, bear fruit to the satisfaction of the people of this country. The foundation of a successful country is a healthy economy, a sound polity, strong institutions and a harmonious society. We are committed to strengthen all these basic foundations of our Republic.

Sir, I have outlined the broad parameters of our economic policy framework. The President's Address refers to seven priority areas and I will draw the attention of the House to these priority areas to give you an idea of what we have been doing and what we plan to do. I recognised yesterday Shri George Fernandesji referred to this matter and said that he did not find a match between what is stated in the President's Address and the Finance Minister's Budget speech. I do not share that perception and I do want to show what we have done and what we propose to do to get this country once again moving on to a high growth path, strong growth in output and employment and a stronger commitment to social equity.

Sir, the Rashtrapatiji has referred to the seven priority areas of our Government - agriculture, employment, education, health care, water, urban renewal and infrastructure. Hon. Members will notice the correlation between these high priority areas and our vision of a prosperous, equitable India. Nobody can deny that it is only by focusing on public and private investment in these seven critical areas can we realise sustainable, equitable growth.

Sir, as I had stated earlier, investment in human capital is essential for an inclusive growth process. The importance we attach to elementary education is apparent from the imposition of an education cess and the priority we give to educational programmes. Simultaneously, we are about to launch the National Rural Health Mission which will not only revamp the public health delivery system but which along with the initiatives in nutrition and education, represents our commitment to human capital formation.

Sir, hon. Members, and even Advaniji referred to the fact that the President's Address makes no mention of rural growth. Sir, that perception is also not correct. We have outlined a programme, a comprehensive programme - *Bharat Nirman* - which attaches high priority to the most important areas which can have a bearing on the polity of rural India.



The "Bharat Nirman" programme outlined both in the President's Address and the Budget speech gives concrete shape to our commitment to achieving tangible outcomes in irrigation, housing, rural roads, drinking water, electricity and telecommunication connectivity by 2009.

Hon. Shri George Fernandesji appeared to have been disappointed that the Budget speech did not adequately elaborate on the reference to "Bharat Nirman" in the President's Address. Sir, "Bharat Nirman" is not a scheme and is not about "Outlays" but about "Outcomes". This is a four year programme of rural infrastructure development. The Finance Minister has identified the following outcomes: namely,

- To bring an additional one crore hectares under assured irrigation;
- To connect all villages that have a population of 1000 (or 500 in hilly/tribal areas) with a road;
- To construct 60 lakh additional houses for the poor;
- To provide drinking water to the remaining 74,000 habitations that are uncovered;
- To reach electricity to the remaining 1,25,000 villages and offer electricity connection to 2.3 crore households; and
- To give telephone connectivity to the remaining 66,822 villages.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Where is the allocation? ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप बजट पर चर्चा के दौरान इस पर बोलिए।

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: This is not fair. So many hon. Members have spoken.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है ?

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Speaker, Sir, the Budget contains enhanced allocations for each of these crucial areas. Having outlined these outcomes, we are committed to making the required outlays.

On the infrastructure front, we face an enormous task. Poor quality infrastructure is the biggest barrier to the growth of industry and trade. We have been working relentlessly in improving the policy regime for investment in infrastructure – be it power, roads, ports, railways, civil aviation, telecommunications. We will increase public investment in crucial areas and supplement that with private investment. Public-Private Partnership will be attempted where possible and appropriate.

The Rural Health Care Mission and the Urban Renewal Mission will facilitate such partnerships. The Urban Renewal Mission will enable the provision of basic amenities in urban areas while at the same time providing world class infrastructure in our cities.

We have outlined water as a priority area. I think, Shri Suresh Prabhu yesterday mentioned about the neglect of water. I plead not guilty. I have listened to the many points raised by hon. Members regarding policies pertaining to water availability and utilization. Sir, I would like to urge hon. Members to impress upon our political leaders at all levels of our democratic governance that we should resist the temptation of playing politics with water. Our Government is committed to providing access to water to all. We have to renew the spirit of cooperation in dealing with this massive challenge.

Sir, an important area of our policy focus is education. Many hon. Members have drawn our attention to the many challenges of access and excellence in education. The National Knowledge Commission that we propose to constitute will focus attention on the quality of our educational system. The issue of access is being addressed by the various programmes we are funding with the Education Cess. Our emphasis on mid-day meals programme is also aimed at improving access to education.

Our Government has been in office now for nine months. And I do wish to point out, as a matter of pride, that India's prestige in the world has never been as high as it is today.

Mr. Speaker, Sir, in the last nine months, the world has been fascinated by the strength and vigour of our democratic processes. We are seen as a shining example of a successful democracy, a polity which periodically redistributes power to reflect the aspirations of our people.

India is today a role model in many ways in managing a multi-racial, multi-religious and a multi-lingual society through effective democratic processes. This is a strength we must all cherish and nurture for this is the strength that enables us to cross all challenges in fulfilling the vision of our founding fathers, a vision, as I said, of an inclusive, just and humane society. The election of the UPA Government last year was a manifestation of the people's mandate for change. We need to respect that and permit our institutions to function effectively. ... (*Interruptions*)

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : नक्सलाइट्स के बारे में क्या हुआ?... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please sit down. You are all senior Members, behaving in this irresponsible manner! Nothing will be recorded unless the Prime Minister yields.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Unless the Prime Minister yields, no comments will be recorded.

DR. MANMOHAN SINGH: I would now like to come to internal security issues, the North-East and Jammu and Kashmir issues, which have been raised by the hon. Members of the Opposition.

Mr. Speaker, Sir, in the nine months in Office, our Government has also worked hard to improve the internal security situation in our country. We have been purposive but humane in bolstering the security environment. We have developed a comprehensive and systematic approach to all internal security issues, whether they be related to Left-wing extremism or militancy in the North East and Jammu and Kashmir.

We are concerned about the spread of Left-wing extremism and it is our sincere assurance that we will work with State Governments in tackling this problem in all its dimensions – political, economic, social and administrative. We will address the underlying causes for disaffection and alienation among sections which tilt towards such extremism. The Union Government is providing assistance to States to meet some of their security-related expenditure and has also decided to bear the cost of deployment of additional Central forces.

Developments in our neighbourhood are also a matter of concern in this regard. Our Government will be taking a lead role in developing a coordinated approach to this problem. Our Government's policy is to engage militants in a dialogue if they abjure the path of violence, to have appropriate and just laws and to modernise security forces so that they can be effective instruments of State action. In this, the Union Government will be a partner with all affected Governments in finding enduring solutions.

Our commitment to a caring society based on the rule of law was reflected in our approach to the situation in the North Eastern region, particularly the State of Manipur. We have reached out to the people with a helping hand, a hand committed to understanding their genuine grievances. The joy, which I saw, on the faces of an unprecedented crowd of Manipuris on the occasion of the handing over of the Kangla Fort gives me the necessary confidence that we are on the right track and that the State can move forward towards normalcy.

Shri Advaniji asked me about the discussions with the NSCN. The negotiations are going on and moving at a pace which is satisfactory. We are in the process of discussing each other's point of view. I am confident that these discussions will be brought to a successful conclusion.

I should also say that until our Government came to power, all these discussions were being held outside the country. Our Government took the view that these discussions must take place within our own country and in that we have succeeded. That alone is a positive development in dealing with problems of the Nagaland.

Sir, our approach to the problems in Jammu and Kashmir has reaped a rich harvest in the manner in which the people of the State came forward to participate in local government election held very recently. The forces of democracy were greatly encouraged by the turn out and the verdict. There has been a perceptibly lower level of violence in the State of Jammu and Kashmir this year. The people are yearning for peace and normalcy. I myself have been twice to the Jammu and Kashmir State. Considerable enthusiasm has been generated by the effective manner in which the reconstruction package has been grounded. The infiltration level has come down by more than 60 per cent during 2004. There is a hope on the horizon and if we keep up the tempo of economic activity there, we may see further improvement in the scenario.

Sir, given the external dimension of terrorism and other trans-border crimes like smuggling of arms, counterfeit currency, drug trafficking, it is very vital to strengthen our international borders. The Government has taken various measures which include fencing of borders, improving road networks in border areas, and deployment of hitech electronic surveillance equipment on the borders.

Sir, I would like to reiterate once again that our Government is not soft on terrorism and militancy. It is, however, willing to realise the inhuman situation created by some of our laws and therefore willing to modify them. We are committed to the National Common Minimum Programme which states that there will be no compromise on terrorism. However, we were equally concerned about the misuse of POTA and we decided to repeal it while enforcing the existing laws more strictly. However, the existing legal framework has been substantially strengthened by amending the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 to handle terrorism related issues more effectively.

Sir, I could go on but in the House no Member has brought up issues of foreign policy. Therefore, I will skip that because of the lateness of the hour. There is, however, one matter that I do wish to refer to and that is our relations with Pakistan. After my meeting with Gen. Musharraf on the side lines of the United Nations General Assembly, all items of composite dialogue are under discussion. We are moving forward and I must say that nothing brings the people of our sub-continent more together than our love for cricket and Bollywood cinema. I am equally conscious of the fact today that even as I speak in this House I am competing for the nation's attention with young men like Sehwag and Kamal. Perhaps that is how it should be. Indeed how nice it would be if we conduct our affairs in this august House with the same spirit of sportsmanship that our young cricketers exhibit on the playing field of the subcontinent.

Sir, when our citizens went to Pakistan for the last Test Series, they returned with tale of bonhomie and warm hospitality. I am delighted to say that our people have returned this hospitality to the thousands of visitors from Pakistan. Relations between nations are after all nothing more than relations between their people. I am sure that time will work to heal our wounds and create an environment of shared prosperity and peace in this subcontinent in which we can all live and work for the greater good of our subcontinent.

Sir, I am happy to inform the hon. Members of the House that I have decided to invite President Musharraf to come to India to watch the cricket match between our two teams. It is my earnest desire that the people in our neighbouring country and their leaders should feel free to visit us whenever they wish to do so. Be it to watch a cricket match; be it to do some shopping; or be it to meet friends and families – India is proud to be an open society and an open economy. I do hope that President Musharraf and his family will enjoy their visit to our country... (*Interruptions*)

Mr. Speaker, Sir, I will be failing in my duty if I do not express my sincere regret at the fact that the proceedings of the House have once again been disrupted in a manner that does not do this House proud... (*Interruptions*)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : What happened today morning?... (*Interruptions*)

DR. MANMOHAN SINGH: I share the sentiments expressed by some Members that our democracy gives us the freedom and the right to express our views without fear or favour and we

must make use of these freedoms in a proper manner. We cannot allow cynicism to grow about the relevance and role of democratic institutions and of elected representatives. There is so much work before us and we have not been able to give our time to it. I share the sentiment of our revered Rashtrapatiji when he said, and I quote:

"The people of India anxiously await your views and your decisions on these crucial economic and social legislation. I urge you, hon. Members, to repay the trust and confidence that the people have reposed in you by dedicating yourselves to the orderly consideration of these Bills. Every minute of Parliament's time is precious and every citizen and taxpayer values it greatly. I sincerely hope you will make the most economical use of the time at your disposal and meet the voter's and the citizen's expectations and fulfil their aspirations."

These were the words of our Rashtrapatiji.

Hon. Members may have genuine concerns that they wish to give expression to in the House. After all, that is what their voters would want them to do. I would be the last one to chastise hon. Members for giving vent to their heartfelt concerns. Yet, there are ways in which we can express these sentiments without disrupting the proceedings of the House... (*Interruptions*)

Mr. Speaker, Sir, I must compliment you in all sincerity for your extreme patience and good humour in dealing with the situation in the House. I am sure the hon. Leader of the Opposition agrees with me that we must all try our best to uphold the dignity and decorum of this august House and never allow anything to happen that would demean it in the eyes of our citizens and the world at large. I appeal once again to all hon. Members to participate actively and effectively in the proceedings of the House, putting forward their views in an appropriate manner.

Mr. Speaker, Sir, I thank you for your indulgence and would like to once again express my gratitude to the President for his thoughtful address. I would like this vote of thanks to the President's Address to be passed unanimously.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Members, now we are going to take up the Motion of Thanks on the Presidents Address.

A number of amendments have been moved by the hon. Members on the Motion of Thanks on the President's Address. Can I put all the amendments to vote of the House together? Or, does any hon. Member want any particular amendment to be moved separately?

**14.00 hrs.**

I shall now put all the amendments together to the vote of the House.

*All the amendments were put and negatived.*

MR. SPEAKER: I shall now put the main motion to the vote of the House.

The question is:

"That an Address be presented to the President in the following terms:-

‘That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 25, 2005’."

*The motion was adopted.*

MR. SPEAKER: Thank you for your cooperation.

The House stands adjourned to meet again at 3 p.m.

**14.01 hrs.**

*The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.*

-----